www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 144 | जौनपुर गुरूवार, 08 जनवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

अमर्त्य सेन को वर्तनी की गलती को लेकर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। निर्वाचन आयोग (ईसी) ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सुनवाई के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। सेन को मतदाता सूची में उनके नाम की वर्तनी में विसंगतियों के कारण कथित तौर पर निर्वाचन आयोग ने बुलाया था। एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा। उन्होंने कहा कि चूंकि बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के पास मतदाताओं के नामों में वर्तनी की गलतियों सहित छोटी–मोटी त्रुटियों को सुधारने का अधिकार है, इसलिए अर्थशास्त्री के मामले में सुधार को स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक रूप से निपटाया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने आज दिन में दावा किया था कि निर्वाचन आयोग ने सेन को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सुनवाई का नोटिस भेजा है। हालांकि, सेन के परिवार के एक सदस्य ने पीटीआई को बताया कि उन्हें आयोग से अभी तक कोई सुनवाई नोटिस नहीं मिला है। अधिकारी ने पीटीआई को बताया, वर्तनी को लेकर जो भ्रम है वह पूरी तरह से तकनीकी है और मतदाता की पात्रता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। हमारे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनावश्यक विवादों से बचने के लिए ऐसे मामलों को प्रशासनिक स्तर पर ही सुलझाएं।

3 करोड़ की नशीली गोलियों के साथ महिला पुलिस के हत्थे चढ़ी

असम, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि कछार जिले में तीन करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिबंधित याबा टैबलेट बरामद होने के बाद एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। इन गोलियों को 'क्रेजी ड्रग' भी कहा जाता है। इनमें 'मेथामफेटामिन' और 'कैफीन' का मिश्रण होता है। भारत में इन पर प्रतिबंध है। शर्मा ने मंगलवार रात 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "गुप्त सूचना के आधार पर कछार पुलिस ने एक महिला को पकड़ा और उसके पास से 20,000 याबा टैबलेट बरामद कीं, जिनकी कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये है।" उन्होंने कहा, "हम असम में मादक पदार्थों के नेटवर्क को जड़ से खत्म कर रहे हैं ताकि हमारे युवाओं को बर्बादी के रास्ते पर जाने से बचाया जा सके। इसके अलावा एक दूसरी घटना के बारे में मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि असम के कछार जिले में मादक पदार्थ के पांच संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और दो करोड़ रुपये की नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। शर्मा ने बताया कि उन्होंने कहा कि जब्त की गई नशीली दवाएं जिले में दो अलग–अलग वाहनों से बरामद की गई हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार रात सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, कछार पुलिस ने सुनाबारीघाट बाईपास पर दो वाहनों को रोककर तलाशी ली।

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए "क्षमता निर्माण" कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया जाए : सीएम आदित्यनाथ

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया जाए। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में 'मिशन कर्मयोगी' के तहत राज्य में अब तक हुई प्रगति और आगामी कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में मिशन के क्रियान्वयन, प्रशिक्षण ढांचे, डिजिटल मंच की स्थिति और विभिन्न विभागों में क्षमता संवर्धन से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा हुई। बयान के मुताबिक, इस दौरान क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान ने उत्तर प्रदेश में मिशन के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मिशन कर्मयोगी' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारतीय संस्कृति के लोकाचार में निहित मूल्यों को आत्मसात करते हुए ऐसे सक्षम मानव संसाधन तैयार करना है, जो प्रदेश और देश के विकास की प्रेरक शक्ति बने। उन्होंने कहा कि यह पहल शासन व्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनाने में निर्णायक भूमिका निभा रही है। बयान के अनुसार, बैठक के दौरान योगी को अवगत कराया गया कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत केंद्र में 30 लाख से अधिक सिविल सेवकों, राज्यों में लगभग 2.2 करोड़ कार्मिकों तथा शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 50 लाख कार्मिकों को क्षमता संवर्धन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सात दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया जाए। साथ ही इसे उनकी पदोन्नति एवं एसीआर (वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट) से भी जोड़ें।

इतिहास के दस्तावेज साझा कर भाजपा ने किया दावा : सुधांशु त्रिवेदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रुख की कड़ी आलोचना की है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ऐतिहासिक आक्रांताओं ने तो मंदिर को केवल भौतिक रूप से लूटा था, लेकिन नेहरू के मन में भगवान सोमनाथ के प्रति सबसे ज्यादा घृणा थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए त्रिवेदी ने नेहरू द्वारा कथित तौर पर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखे गए एक पत्र को साझा किया। त्रिवेदी ने दावा किया कि, इस पत्र में नेहरू ने खान को श्प्रिय नवाबजादाश् कहकर संबोधित किया और सोमनाथ के दरवाजों की कथा को पूरी तरह झूठा बताया। भाजपा नेता का तर्क है कि यह पत्र एक प्रकार का आत्मसमर्पण था, जिससे यह संकेत मिलता है कि नेहरू ने भारत की सभ्यतागत विरासत की रक्षा करने के बजाय मंदिर के पुनर्निर्माण को कम महत्व देने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के दुष्प्रचार का सामना करने के स्थान पर नेहरू ने पड़ोसी देश को खुश करने के लिए हिंदू ऐतिहासिक प्रतीकों को कमतर आंका। त्रिवेदी ने दावा किया कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पूर्णतः विरोध किया था। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मंत्रिमंडल के सहयोगियों को पत्र लिखकर मंदिर के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर प्रश्न उठाए थे और उन्हें उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की सलाह दी थी।

भारत को आत्मनिर्भर बनने में मजबूती देगा : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप अब चालू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस जहाज के शुरू होने से भारत की आत्मनिर्भरता और मजबूत हुई है। इसके साथ ही यह दिखाता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को जहाज समुद्र प्रताप का शुभारंभ किया। यह भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। यह अब तक तटरक्षक बल के बेड़े का सबसे बड़ा जहाज है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ष्भारतीय तटरक्षक पोत (आईसीजीएसप्) समुद्र प्रताप का कमीशन होना कई कारणों से उल्लेखनीय है। जिनमें यह तथ्य भी शामिल है कि यह आत्मनिर्भरता के हमारे दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करता है। हमारे सुरक्षा तंत्र को बढ़ावा देता है और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने, समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव अभियानों और भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। इस पोत की प्राथमिक भूमिका समुद्र में प्रदूषण से निपटने की है, जिसे अत्याधुनिक प्रणालियों द्वारा समर्थित किया जाता है, जिनमें साइड–स्वीपिंग आर्म्स, फ्लोटिंग बूम, उच्च क्षमता वाले स्किमर, पोर्टेबल बजरा और एक प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला शामिल हैं। इस जहाज में एक बाहरी अग्निशमन प्रणाली भी लगी हुई है और स्वचालन और मिशन दक्षता को बढ़ाने के लिए इसमें डायनेमिक पोजिशनिंग, एकीकृत ब्रिज सिस्टम, एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली और स्वचालित पावर प्रबंधन प्रणाली जैसी उन्नत प्रणालियां एकीकृत की गई हैं।

पुराने रिश्तों का सम्मान, बातचीत से निकले समाधान : जयशंकर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों को लेकर चिंतित है, जहां पिछले सप्ताहांत अमेरिका ने हवाई हमले किए और एक साहसी ऑपरेशन में तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। जयशंकर ने सभी पक्षों से बैठकर एक ऐसा समाधान निकालने का भी आग्रह किया जो वेनेजुएला के लोगों के हित में हो। लक्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत के वेनेजुएला के साथ कई सालों से अच्छे संबंध रहे हैं। जयशंकर ने कहा, ष्मुझे लगता है कि हमने कल (सोमवार) एक बयान जारी किया था, मैं आपसे उसे देखने का आग्रह करूंगा। जो हुआ – अगर मैं बयान को संक्षेप में कहूं – तो हम घटनाक्रमों को लेकर चिंतित हैं। लेकिन, हम वास्तव में इसमें शामिल सभी पक्षों से आग्रह करेंगे कि वे अब बैठकर एक ऐसी स्थिति पर पहुंचें जो वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के हित में हो। आखिरकार, यही हमारी चिंता है। उन्होंने आगे कहा, ष्हम वेनेजुएला को एक ऐसे देश के रूप में देखना चाहते हैं जिसके साथ, कई–कई सालों से, हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हम चाहते हैं कि घटनाओं की दिशा कुछ भी हो, लोग ठीक रहें। सोमवार को एक बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय हैं और कहा कि सरकार बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। ष्भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करता है। हम सभी संबंधित पक्षों से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। बयान में कहा गया है कि कराकस में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और सभी संभव सहायता देना जारी रखेगा। सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों से बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला की गैर–जरूरी यात्रा से बचने के लिए कहा गया है। इसने वेनेजुएला में नागरिकों को भी अत्यधिक सावधानी बरतने और इस लैटिन अमेरिकी देश में आवाजाही सीमित करने की सलाह दी है।

संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन : फडणवीस

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंबरनाथ और अकोला में कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस –ए– इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएम आईएम) के साथ गठबंधन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए इस गठबंधन को खारिज किया है। अंबरनाथ में भाजपा ने कांग्रेस और अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन कर नगर परिषद का अध्यक्षता बनाया है। वहीं अकोट नगर परिषद में भाजपा ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है। सीएम फडणवीस ने स्थानीय भाजपा इकाई के इस कार्य को संगठन विरोधी बताया है। साथ ही कड़ी नाराजगी जताते हुए ऐसे गठबंधन को तुरंत खत्म करने के बाद पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। गठबंधन को खारिज करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस तरह के किसी भी तरह के गठबंधनों को पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की मंजूरी नहीं है। यह संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन है। अपने बयान में सीएम ने कहा कि भाजपा कभी भी कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं कर सकती। ऐसे गठबंधन अस्वीकार्य हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने बयान में कहा कि ऐसे गठबंधन को को रद्द करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं और यह भी कहा कि इसमें शामिल नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, श्यदि भाजपा के किसी भी स्थानीय नेता ने बिना अनुमति के इन पार्टियों (एआईएमआईएम, कांग्रेस) के साथ गठबंधन किया है, तो यह पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठाणे जिले के अंबरनाथ नगर परिषद में भाजपा ने कांग्रेस और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ मिलकर श्अंबरनाथ विकास अघाड़ीश के बैनर तले नगर परिषद का नेतृत्व संभाला और सहयोगी शिवसेना को दरकिनार कर दिया। भाजपा पार्षद तेजश्री करंजुले पाटिल बुधवार को शिवसेना की मनीषा वालेकर को हराकर परिषद अध्यक्ष चुनी गईं। 20 दिसंबर को हुए 60 सदस्यीय अंबरनाथ नगर परिषद के चुनावों में, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो बहुमत से चार सीटें कम थी। भाजपा ने 14 सीटें, कांग्रेस ने 12, एनसीपी ने चार सीटें जीतीं और दो निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचित हुए।

जम्मू–कश्मीर में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक

जम्मू, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू–कश्मीर पर एक हाई–लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू–कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीएपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।यह रिव्यू मीटिंग 2026 में केंद्र शासित प्रदेश पर पहली हाई–लेवल सुरक्षा रिव्यू मीटिंग होगी। यह मीटिंग जम्मू क्षेत्र के पर्वतीय और दूरदराज के इलाकों में जम्मू–कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों द्वारा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन्स के बाद हो रही है।अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री की मीटिंग के दौरान, सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों के साथ–साथ जम्मू–कश्मीर के मुश्किल, दुर्गम इलाकों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने और साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने की समन्वित रणनीति पर चर्चा की जाएगी।जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, होम सेक्रेटरी चंद्रकर भारती, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात और इंटेलिजेंस चीफ नीतीश कुमार समेत टॉप पुलिस और सिविल अधिकारी मीटिंग में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और सभी सीएपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रमुख भी रिव्यू मीटिंग में शामिल होंगे। उम्मीद है कि सीनियर अधिकारी गृह मंत्री को स्थिति के अलग–अलग पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें सर्दियों के दौरान एलओसी और आईबी पर जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम और जम्मू–कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करना शामिल है।

केसीआर को लेकर आपत्तिजनक बयान पर बीआरएस ने रेवंत और राहुल पर साधा निशाना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस और बीआरएस के बीच तीखी नोकझोंक मंगलवार को और तेज हो गई, जब भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने कहा कि चुनावी वादों को पूरा नहीं करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी फांसी के हकदार हैं। रामा राव की यह टिप्पणी मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के हालिया बयान के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और उनके भतीजे टी हरीश राव को पिछली बीआरएस सरकार के दौरान नदी जल विवाद में तेलंगाना के साथ हुए अन्याय के लिए फांसी'' देना गलत नहीं होगा। वे जिला मुख्यालय जंगांव में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। रामा राव ने कहा कि क्या तेलंगाना राज्य का दर्जा दिलाने और किसानों के लिए रायथु बीमा योजना और रायथु बंधु निवेश सहायता योजना तथा मिशन भागीरथा पेयजल आपूर्ति योजना सहित कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर के नाम से भी जाना जाता है, को फांसी दी जानी चाहिए? रामाराव ने कहा, असल में किसे फांसी दी जानी चाहिए? राहुल गांधी वारंगल आए थे। उन्होंने किसानों की बैठक बुलाई। किसानों ने कहा कि केसीआर रायथु बंधु योजना के तहत 10,000 रुपये दे रहे हैं। हम 15,000 रुपये देंगे। क्या उन्होंने दिए? उन्होंने दो फसलों के लिए भी नहीं दिए।

राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को लेकर पीएम को घेरा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उन पर ष्दबावष में ष्सरेंडरष करने का आरोप लगाया। गांधी की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने हाउस ळव्व मेंबर रिट्रीट में बोलते हुए दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे मिलने का समय मांगा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि ''फर्क समझो, सर जी।'' लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने पिछले साल जून में कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' से संबंधित एक कार्यक्रम में दिए गए अपने भाषण का एक अंश साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप के एक फोन से उनके सामने झुक गए तथा ''नरेन्दर, सरेंडर'' कर गए। उस भाषण में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस तथा उसके नेताओं ने महाशक्तियों के सामने कभी 'सरेंडर' नहीं किया, लेकिन थोड़े से दबाव के आगे झुक जाना ही भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल स्वभाव है। कांग्रेस नेता ने बुधवार को अपने इस भाषण से संबंधित वीडियो 'एक्स' पर साझा करते हुए पोस्ट किया, ''फर्क समझो, सर जी। दरअसल, ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ (शुल्क) को लेकर हाल के दिनों में कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जो सरकार को असहज करने वाली हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल इन टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ट्रंप की टिप्पणियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्रंप के वक्तव्य का वीडियो साझा करते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''नमस्ते ट्रंप से लेकर हाउडी मोदी तक, 'डोनाल्ड भाई' और अब यह (सर)। आगे क्या?'' अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा कि रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनसे 'ज्यादा खुश नहीं हैं।' ट्रंप ने 'हाउस जीओपी सदस्य रिट्रीट' में अपने संबोधन में यह भी दावा किया, ''प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और बोले, ''श्रीमान्, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?' मैंने कहा, ''जी हां।

संपादकीय

वोट खरीद की योजनाएं

बुजुर्गों को पेंशन मिले, यह कल्याणकारी सोच है। मगर ऐसी सामाजिक सुरक्षा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को क्यों मिलनी चाहिए? सरकारी कर्मचारियों को एक अलग सुविधा–प्राप्त वर्ग के रूप में रखने के प्रयासों के दुष्परिणाम पहले भी सामने आ चुके हैं। बिहार की तर्ज पर असम सरकार ने भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में रुपया भेजने की योजना घोषित की है। वहां इसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना कहा जाएगा। इसके तहत 37 लाख महिलाओं के खाते में 8000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ राज्य के खजाने पर आएगा। अगले अप्रैल– मई में विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में भी होना है। तो वहां सरकार ने पहले अपने कर्मचारियों को लुभाने की योजना घोषित की है। तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिटायर्ड होने वाले राज्य सरकार के हर कर्मचारी को कम से कम अपने आखिरी वेतन का 50 फीसदी हिस्सा बतौर पेंशन मिले। इसके लिए कर्मचारी को सिर्फ दस फीसदी योगदान करना होगा। अतिरिक्त सारा बोझ राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही रिटायर हो रहे कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक ग्रैच्युटी मिले, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल इन योजनाओं से राज्य सरकार पर 13 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। चूंकि पेंशन की रकम महंगाई दर के अनुपात में बढ़ेगी, इसलिए यह खर्च हर गुजरते वर्ष के बढ़ता जाएगा। कहना कठिन है कि सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की इस कोशिश का कितना चुनावी लाभ सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिलेगा, मगर इस प्रयास में जो देनदारी बनेगी, उसका बोझ आने वाली सभी सरकारों को उठाना होगा। पेंशन के रूप में बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा मिले, यह कल्याणकारी सोच है। मगर ऐसी सुरक्षा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को क्यों मिलनी चाहिए? सरकारी कर्मचारियों को एक अलग सुविधा–प्राप्त वर्ग के रूप में रखने के प्रयासों के दुष्परिणाम पहले सामने आ चुके हैं। उसका समाधान नई पेंशन व्यवस्था से ढूंढा गया था। तमिलनाडु सरकार (इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं), उस व्यवस्था को पलटने जा रही है। चुनाव से ठीक पहले ऐसा कदम समस्याग्रस्त है। बेहतर नजरिया यह होता कि समाज के सभी तबकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में कदम उठाया जाता। आखिर सरकारी कर्मचारी भी समाज की ही हिस्सा हैं। उन्हें अलग वर्ग में रखकर राजनीतिक दल खराब मिसाल पेश कर रहे हैं।

हैरान करती है सरकार और न्यायपालिका की यह जुगलबंदी

अनिल

राज्यपालों के जरिए राज्यों के अधिकार क्षेत्र में केंद्र के दखल की शिकायतें हाल के वर्षों में बढ़ती चली गई हैं। विधानसभाओं से पारित ऐसे विधेयक, जिनसे केंद्र सहमत न हो, उन्हें कानून न बनने देने के लिए राज्यपालों ने उन पर दस्तखत न करने का तरीका अपनाया है। अतरू इससे परेशान गैर–एनडीए शासित राज्य सरकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल के फैसले को बड़ी राहत माना गया। पांच दशक पहले आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो महज मंशा जाहिर की थी कि न्यायपालिका सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, लेकिन उनकी यह मंशा पिछले कुछ वर्षों से मूर्तरूप लेती दिख रही है। सर्वोच्च और उच्च अदालतों के न्यायाधीश न सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हुए प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उनके फैसले भी सरकार और सत्तारूढ़ दल की मंशा के मुताबिक आ रहे हैं। ऐसा सिर्फ संवैधानिक और नीतिगत मामलों में ही नहीं बल्कि गंभीरतम आपराधिक मामलों में भी हो रहा है। यह भी कम चिंताजनक बात नहीं है कि अगर सर्वोच्च अदालत की ओर से कोई फैसला सरकार की मंशा के मुताबिक नहीं आता है तो सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से फैसला देने वाले जज पर देशविरोधी होने का आरोप तक लगा दिया जाता है (संदर्भ रू भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे का 20 अप्रैल 2025 को लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना पर आरोप) ।हाल के कुछ वर्षों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पता चलता है कि सर्वोच्च अदालत और कुछ उच्च अदालतों ने भाजपा नेताओं और भाजपा से करीबी संबंध रखने वाले कारोबारियों, पूर्व नौकरशाहों व अन्य लोगों को राहत देने और विपक्षी पार्टियों के नेताओं की नकेल कसने में कोई कोताही नहीं बरती है। अपवाद के तौर पर भी किसी भाजपा नेता या भाजपा से जुड़े व्यक्ति को अदालत ने निराश नहीं किया है। गंभीर से गंभीरतम आपराधिक मामलों में फंसे जिस भी व्यक्ति ने राहत मांगी है, उसे राहत मिली है। उसी तरह अपवाद स्वरूप किसी विपक्षी नेता या सरकार से असहमत किसी व्यक्ति को राहत मिलना तो दूर, उल्टे उसे अदालत की सख्ती का सामना करना पड़ा है।पिछले कुछ दिनों में ही न्यायपालिका के कुछ फैसले ऐसे आए हैं, जिनसे न सिर्फ न्यायापालिका पर से लोगों का विश्वास उठा है बल्कि यह भी आभास हुआ है कि न्यायपालिका भी अब सरकार का ही हिस्सा बन गई है। पिछले नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के एक बहुचर्चित मामले के अभियुक्तों को कुछ पैसा बैंक को चुकाने का निर्देश देकर मामला खत्म करने की इजाजत दे दी। स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड कंपनी के मालिक संदेसरा बंधुओं पर 14,000 करोड़ रुपये के घपले का आरोप है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वे 5,100 करोड़ रुपये का भुगतान कर गंभीर आरोपों में चल रहे मुकदमों से मुक्त हो जाएं। नितिन एवं चेतन संदेसरा उन भगोड़ों में हैं, जो वित्तीय संस्थाओं को भारी चूना लगा कर देश से भाग निकले। चेतन की पत्नी दीप्ति और उनके परिवार के सदस्य हितेश पटेल को भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। सवाल यह है कि क्या भारतीय न्याय प्रणाली के तहत किसी व्यक्ति को वित्तीय जुर्माना चुका कर आपराधिक अभियोग से मुक्त होने का अवसर दिया जाना चाहिए? इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि इसे भविष्य के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। जो भी हो, संदेसरा बंधुओं को यह लाभ मिला है, तो आखिर किस तर्क पर विजय माल्या या नीरव मोदी या वैसे अन्य आर्थिक अभियुक्तों को इससे वंचित रखा जा सकता है?ऐसे ही एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया (वीआई) कंपनी पर बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) की कुल रकम का पुनर्मूल्यांकन करने और उसे माफ करने की अनुमति केंद्र को दे दी है। यह फैसला भी पिछले नवंबर महीने में ही आया और उसी दिन आयकर विभाग ने ट्रांसफर प्राइसिंग केस में इस कंपनी पर 8,500 करोड़ रुपये के बकाया से संबंधित मुकदमे को वापस ले लिया। 2020 के न्यायिक निर्णय के मुताबिक वीआई पर 58,254 करोड़ रुपये का बकाया एजीआर तय किया गया था। ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज के साथ यह रकम 83,400 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। अब यह सारी रकम माफ की जा सकेगी। दरअसल, जब कभी ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो उसके लिए तर्क गढ़ लिए जाते हैं। रोजगार बचाना एक आम दलील है। वीआई के मामले में यह भी कहा गया कि अगर कंपनी +फेल हुई, तो बाजार में जियो और एयरटेल का द्वि–अधिकार हो जाएगा। मगर भारत सरकार को द्वि या एकाधिकार से कोई दिक्कत है, इसे मानने का शायद ही कोई आधार मौजूद हो! असल मकसद है अपनी अक्षमताओं के कारण नाकाम हो रही एक कंपनी को बचाना। जाहिर है कि ऐसे कदम याराना पूंजीवाद के दायरे में आते हैं। मगर आज इसकी शायद ही किसी को ि‍फक्र हो। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं।कानून यह है कि कोई किसी भी निर्माण परियोजना पर काम पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिलने के बाद ही होना चाहिए। मगर सरकार ने पहले 2017 में एक अधिसूचना और फिर 2021 में ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से प्रावधान कर दिया कि बिना पर्यावरण संबंधी हरी झंडी लिए जिन परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ चुका है, उन्हें बाद में ऐसी मंजूरी दी जा सकेगी। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस वर्ष मई में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया। दो जजों की बेंच ने उचित निर्णय दिया कि ऐसा करना कानून और उसकी भावना के खिलाफ है। मगर चूंकि इस फैसले से बड़े–बड़े हित प्रभावित हो रहे थे, तो पुनरीक्षण याचिका पर कोर्ट ने तीन जजों की बेंच बनाई। उस बेंच ने 2–1 के बहुमत से मई में दिए गए फैसले को पलट दिया है। यानी पर्यावरण मंजूरी की बिना परवाह किए काम शुरू करो और बाद में मंजूरी ले लो– यह चलन जारी रहेगा। संदेश साफ है, जब धनी–मानी लोगों के हित जुड़े हों तो अक्सर कानून की परिभाषा बदल जाती है!इससे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में अपने ही एक फैसले को पलट दिया है। बल्कि उससे भी आगे जाते हुए तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने व्यवस्था दे दी कि राज्यपाल के विधेयकों को लटकाए रखने जैसे मामलों को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। यानी बीते अप्रैल में तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में खुद उसने जो निर्णय दिया, उसके बारे में अब उसकी राय है कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व्यवस्था दी! तब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए कहा था कि विधानसभाओं से दोबारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों को 90 दिन के अंदर सहमति देनी होगी।

कार्तिगई दीपम विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला सनातन विरोधियों की करारी हार है

नीरज

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी के दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसे रोकने का कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। अदालत ने साथ ही राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था के नाम पर लगाए गए प्रतिबंधों को निराधार और कल्पनाजन्य करार दिया। न्यायालय ने कहा कि जिस स्थान पर दीपम जलाया जाता है वह मंदिर से जुड़ी पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा रहा है। केवल आशंका के आधार पर किसी धार्मिक परंपरा को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि धार्मिक स्वतंत्रता केवल निजी पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि सामूहिक और सार्वजनिक धार्मिक अभिव्यक्तियां भी इसके अंतर्गत आती हैं। हम आपको बता दें कि इस मामले में राज्य सरकार ने दलील दी थी कि दीपम जलाने से सामाजिक तनाव और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन का दायित्व भय पैदा करना नहीं बल्कि निष्पक्ष और साहसिक ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि हर परंपरा को संभावित विवाद के नाम पर रोक दिया जाए तो संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता केवल कागज पर रह जाएगी। हम आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क रखा गया था कि कार्तिगई दीपम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसे रोकने का प्रयास समाज में अनावश्यक विभाजन और असंतोष को जन्म देता है। कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई और आदेश दिया कि परंपरागत रीति से दीपम जलाने की अनुमति दी जाए। देखा जाये तो मद्रास हाईकोर्ट का यह निर्णय उस मानसिकता पर करारा प्रहार है जो हर हिंदू परंपरा को कानून व्यवस्था के नाम पर कटघरे में खड़ा करने की आदी हो चुकी है। आज सवाल यह नहीं है कि दीपम जलेगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को हर बार डर और शक के चश्मे से देखा जाएगा? तमिलनाडु की द्रमुक सरकार का तर्क कि दीपम जलाने से अशांति फैल सकती है, दरअसल प्रशासनिक असफलता को छिपाने का तरीका है। अगर हर धार्मिक आयोजन से पहले सरकार को डर लगने लगे तो फिर शासन चलाने का नैतिक अधिकार किस बात का रह जाता है? अदालत ने ठीक ही कहा कि कल्पित भय के आधार पर मौलिक अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता। देखा जाये तो यह मामला उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां हिंदू धार्मिक परंपराओं को बार बार रोकने और सीमित करने का प्रयास किया जाता है। कभी शोर का बहाना बनाया जाता है, कभी पर्यावरण का तो कभी कानून व्यवस्था का। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यही तर्क अन्य समुदायों के मामलों में अचानक गायब हो जाते हैं। यह दोहरा मापदंड समाज में असंतोष और अविश्वास को जन्म देता है। कार्तिगई दीपम का सामाजिक महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं है। यह पर्व सामूहिकता का प्रतीक है। पहाड़ी पर जलता दीप दूर दूर तक दिखाई देता है और समाज को जोड़ने का काम करता है। जब ऐसी परंपराओं को रोका जाता है तो संदेश जाता है कि बहुसंख्यक समाज की भावनाएं गौण हैं। यही भावना धीरे धीरे आक्रोश में बदलती है और फिर वही आक्रोश सामाजिक तनाव का रूप ले लेता है। इस फैसले का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि लोगों का यह विश्वास और प्रबल हुआ है कि न्यायपालिका संविधान की आत्मा को समझती है। अदालत के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य केवल एक धर्म के प्रति कठोर हो जाए और बाकी के प्रति नरम। सच्ची धर्मनिरपेक्षता सभी परंपराओं के साथ समान व्यवहार की मांग करती है। यह निर्णय प्रशासन के लिए भी चेतावनी है। उसे समझना होगा कि परंपराओं को दबाने से शांति नहीं आती बल्कि असंतोष भीतर ही भीतर सुलगता रहता है। बहरहाल, अगर आज अदालत ने दीपम जलाने के अधिकार की रक्षा नहीं की होती तो कल कोई और परंपरा इसी तरह प्रतिबंधों की भेंट चढ़ जाती। वैसे यह फैसला केवल एक धार्मिक जीत नहीं है। यह सांस्कृतिक आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। यह संदेश है कि डर के नाम पर अधिकार छीने नहीं जा सकते। यह आदेश यह भी संदेश देता है कि अगर समाज चुप रहा तो उसकी परंपराएं एक एक कर खत्म कर दी जाएंगी। दीप तो अब जल जायेगा लेकिन समाज की चेतना की लौ भी जलती रहनी चाहिए क्योंकि संभव है राह में रोड़े अटकाने वाले दूसरा प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार बैठे हों।

मोदी–शाह फॉर्मूले के हिंदी क्षेत्र के बाहर सबसे कठिन परीक्षा का समय

आर. सूर्य

आर्थिक रूप से, तमिलनाडु भाजपा की पसंदीदा पिच को और कमजोर करता है। यह राज्य भारत की जीडीपी में लगभग 9 प्रतिशत का योगदान देता है। यहां प्रति व्यक्ति आय 2.8 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है, और इसने दशकों से एक द्रविड़ ढांचे के जरिए कल्याण किया है, जो मोदी के आने से बहुत पहले का है। यहां के मतदाता राष्ट्रीय बदलाव की तलाश में नहीं हैं। वे बंटवारे, सम्मान और स्वायत्तता पर बातचीत कर रहे हैं। एक दशक से ज्यादा समय से, भारतीय चुनाव एक धोखे से भरे आसान फॉर्मूले के इर्द–गिर्द घूम रहे हैं–नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर शो करते हैं, अमित शाह चुनावी गणित को सटीक बनाते हैं। एक कहानी पर हावी रहता है, दूसरा मशीन को कंट्रोल करता है। फिर भी 2026 उस सबसे असुविधाजनक सच्चाई – राष्ट्रीय प्रभुत्व अपने आप क्षेत्रीय शक्ति में नहीं बदलता – को उजागर करने का खतरा दरपेश करता है जिससे भाजपा सावधानी से बचने की कोशिश करती रही है।पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर नहीं करेंगे, या पार्टी पर अमित शाह की पकड़ को ढीला नहीं करेंगे। मोदी राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी रूप से अजेय बने हुए हैं। संगठन पर शाह का नियंत्रण लगभग पूरा है। लेकिन ये चुनाव उस मिथक को तोड़ सकते हैं जिसे भाजपा ने एक दशक तक पाला–पोसा हैकि ब्रांड मोदी हर जगह, संस्कृतियों, भाषाओं, जाति संरचनाओं और राजनीतिक परंपराओं में चुनावी रूप से अजेय हैं। यहीं, नई दिल्ली में नहीं, मोदी–शाह प्रोजेक्ट को सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है।भाजपा के पसंदीदा पैमानों के अनुसार, पार्टी अजेय दिखती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर लगभग 36.5 प्रतिशत था, जिससे वह भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। अर्थव्यवस्था 6.7–7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, महंगाई कम हुई है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 18 राज्यों पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। विपक्ष खंडित, वैचारिक रूप से असंगत और रणनीतिक रूप से विभाजित है। लेकिन चुनाव राष्ट्रीय औसत पर नहीं लड़े जाते। वे विशिष्ट सामाजिक गठबंधनों, ऐतिहासिक यादों और स्थानीय शक्ति संरचनाओं के भीतर जीते या हारे जाते हैं।बाकी सभी जगहों पर, मोदी–शाह ब्रांड को गहरी सांस्कृतिक, जातिगत और भाषाई बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिन्हें केंद्र में बारह साल की लगातार सत्ता भी खत्म करने में विफल रही है। भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा खुलासा करने वाला केस स्टडी है। 2011 और 2021 के बीच, पार्टी का वोट शेयर 10 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 38 प्रतिशत हो गया – जो भाजपा के इतिहास में सबसे तेज चुनावी विस्तार में से एक है। फिर भी, 2021 में, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 48 प्रतिशत वोट और 294 में से 213 विधानसभा सीटों के साथ इस चुनौती को कुचल दिया।भाजपा ने आक्रामक तरीके से ध्रुवीकरण किया है, बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाया है और एक दशक से ज्यादा समय से संगठनात्मक पूंजी लगाई है। लेकिन बंगाल की राजनीति सिर्फ वैचारिक जोर से तय नहीं होती। यह कल्याणकारी योजनाओं, अत्यधिक स्थानीय संरक्षण नेटवर्क और बंगाली उप–राष्ट्रवाद की गहरी जड़ें वाली भावना से आकार लेती है।बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 27–28 प्रतिशत है। तृणमूल कांग्रेस को उनमें से लगभग दो–तिहाई से तीन–चौथाई लोगों का समर्थन हासिल है। इसमें महिला मतदाताओं को भी जोड़ दें – जो मतदाताओं का लगभग 49 प्रतिशत हैं – जिन्हें लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के जरिए टीएमसी के कल्याणकारी शासन तंत्र में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया गया है, और भाजपा की सीमा साफ हो जाती है। ब्रांड मोदी रैलियों में जोश भर सकता है, लेकिन बंगाल में चुनाव पोडियम से नहीं जीते जाते। वे नगर निगम कार्यालयों, राशन की दुकानों और मोहल्ला समितियों में जीते जाते हैं – ऐसी जगहें जहां भाजपा अभी भी एक शासी विकल्प से ज्यादा एक जोरदार बाहरी पार्टी की तरह दिखती है। अगर बंगाल भाजपा की सीमाओं को उजागर करता है, तो तमिलनाडु उसकी धारणाओं को अपमानित करता है। एनडीए गठबंधन, लगातार केंद्रीय अभियानों, और राष्ट्रीय पहचान के बावजूद, तमिलनाडु में भाजपा का वोट शेयर 3 से 6 प्रतिशत के बीच अटका हुआ है। 2021 में भी, अन्नाद्रमुक गठबंधन के सहारे, एनडीए को 234 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 23 सीटें मिलीं। यह मैसेजिंग की विफलता नहीं है। यह तालमेल की विफलता है।उच्च जातियां तमिलनाडु की आबादी का मुश्किल से 3–4 प्रतिशत हैं। ओबीसी और एमबीसी मिलकर मतदाताओं का लगभग दो–तिहाई हिस्सा हैं। यहां द्रविड़ राजनीति वैचारिक दिखावा नहीं हैय यह राजनीतिक सामान्य ज्ञान है, जो रोजमर्रा के शासन और सामाजिक पहचान में गहराई से जुड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से, तमिलनाडु भाजपा की पसंदीदा पिच को और कमजोर करता है। यह राज्य भारत की जीडीपी में लगभग 9 प्रतिशत का योगदान देता है। यहां प्रति व्यक्ति आय 2.8 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है, और इसने दशकों से एक द्रविड़ ढांचे के जरिए कल्याण किया है, जो मोदी के आने से बहुत पहले का है। यहां के मतदाता राष्ट्रीय बदलाव की तलाश में नहीं हैं। वे बंटवारे, सम्मान और स्वायत्तता पर बातचीत कर रहे हैं। केरल की आबादी बहुत की संरचना मुश्किल है। आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 27 प्रतिशत है, और ईसाइयों की लगभग 18 प्रतिशत। लगभग 45 प्रतिशत मतदाता अल्पसंख्यक हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय वैचारिक प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा शक करते हैं। असम की राजनीति बहुत ज्यादा स्थानीय है – जो जातीयता, जमीन के अधिकार, प्रवासन की चिंताओं और पहचान के संघर्षों से तय होती है। मुसलमानों की संख्या, जो अनुमानित 34–35 प्रतिशत है, भाजपा की पहुंच से काफी हद तक बाहर है। पार्टी शर्मा के अति–स्थानीय नेतृत्व में असमिया हिंदुओं, ओबीसी और आदिवासी समूहों को एकजुट करके इसकी भरपाई करती है। यह मॉडल हर जगह लागू नहीं हो सकता। इसके लिए एक प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता की जरूरत होती है – जिसकी भाजपा में, ज्यादातर गैर–हिंदी राज्यों में, साफ तौर पर कमी है। यह भाजपा की सबसे असहज संरचनात्मक समस्या है। इसके राष्ट्रीय गठबंधन – उच्च जातियां और ओबीसी का एक हिस्सा ने हिंदी भाषी राज्यों में शानदार ढंग से काम किया है। लेकिन जिन राज्यों में उच्च जातियां आबादी का 10 प्रतिशत से कम हैं और सामाजिक न्याय की राजनीति हिंदुत्व से पहले से मौजूद है, वहां यह फॉर्मूला फेल हो जाता है। राजनीति में बारह साल बहुत लंबा समय होता है। अगर केंद्र में लगातार दस साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल में सेंध नहीं लगा पाती है, तो समस्या नेतृत्व, कोशिश या संसाधनों की नहीं है। यह ढांचागत दोष की समस्या है।

क्या रूसी लोग युद्धखोर हैं?

शंकर शरण

रूसी इतिहास में युद्ध सदियों से बार–बार की परिघटना है। अमेरिकी इतिहासकार प्रो. ग्रेगोरी कार्लटन ने अपनी पुस्तक रसिया द स्टोरी ऑफ वारश (2017) में रूसी इतिहास का एक रोचक आकलन किया है। ज् ऐतिहासिक रूप से रूसियों के लिए युद्ध उन के अस्तित्व का सामान्य अंग रहा है। रूसी सैन्य अकादमी के प्रमुख रहे निकोलाई सुखोतिन ने उन्नीसवीं सदी के अंत में हिसाब लगाकर बताया था कि उस से पिछली पाँच सदियों में रूस का लगभग दो तिहाई समय युद्ध लड़ते बीता है। उस के बाद, आगे बीसवीं सदी का हिसाब तो ऊपर देख ही चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस–उक्रेन युद्ध के जल्द ही खत्म होने का दावा किया है। पर रूसी राष्ट्रपति पूतिन जल्दी में नहीं लगते। न ही उक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की बहुत अधीर लगते हैं। इसीलिए कूटनीतिक बात–चीत में प्रगति जरूर हो रही है, पर ट्रंप का दावा अधिक विश्वसनीय नहीं लगता। इसलिए भी, कि कुछ ही पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पूतिन को श्पागलत्र कहा था। क्योंकि उन्होंने फटाफट ट्रंप की बात मान उक्रेन से युद्ध खत्म नहीं किया। पर ट्रंप रूसियों का चरित्र नहीं जानते। वे रूस के इतिहास से भी अनजान लगते हैं। यह कुछ स्वाभाविक भी है। अमेरिकियों द्वारा युद्ध को अपवाद, असहज घटना सा लिया जाता है। संभवतरू कारण यह भी हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कभी विदेशी कब्जा नहीं झेला है। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम, दोनों में मिलाकर भी कुल पाँच लाख अमेरिकी सैनिक मारे गये। लेकिन उसी से अमेरिकी काफी खिन्न हुए थे। आज तक उस की मनोवैज्ञानिक स्मृति वहाँ की रचनाओं में आती रहती है। परन्तु रूसी इतिहास में युद्ध सदियों से बार–बार की परिघटना है। अमेरिकी इतिहासकार प्रो. ग्रेगोरी कार्लटन ने अपनी पुस्तक श्रसियारू द स्टोरी ऑफ वारत्र (2017) में रूसी इतिहास का एक रोचक आकलन किया है। उस से पता चलता है अब तक रुसियों ने अनेक ऐसे युद्ध झेले जो मानो रूसियों को समूल खत्म कर देने लिए हुए थे। केवल द्वितीय विश्व युद्ध में ही 2 करोड़ से अधिक रूसी मारे गये थे, जबकि पूरे देश की आबादी 17 करोड़ थी। हिटलर ने सचमुच रूसियों के खात्मे के लिए ही लेनिनग्राद पर घेरा डाला था। वह लेनिनग्राद पर कब्जा कर सकता था, परन्तु उस ने सितंबर 1941 से जनवरी 1944, ढाई साल तक, उस शानदार नगर की घेरेबंदी कर तमाम रूसियों को भूख से मार डालना तय किया था! उसे झेल कर तमाम रूसी लड़ते रहे। अंत में बर्लिन तक जाकर हिटलर को हराया। उस युद्ध के चार साल में रूस की संपूर्ण युवा पुरूष आबादी के तीन चौथाई से अधिक मारे गये! वह रूस के लिए वैसा अपवाद युद्ध भी न था। उस से पहले प्रथम विश्व युद्ध, कम्युनिस्ट क्रांति, और गृह–युद्ध कृ यानी 1914 से 1921 के बीच कृ मात्र छरू–सात वर्ष में 1 करोड़ रूसी मारे गये थे। जबकि रूस की कुल आबादी मात्र 18 करोड़ थी। और पीछे जाएं, तो 1812 में नेपोलियन की महान सेना ने मास्को को जलाकर राख कर दिया था। वह फ्रांसीसी सेना तब तक यूरोपीय इतिहास में सब से बड़ी थी! लेव टॉलस्टाय का कालजयी उपन्यास श्वार एंड पीसत्र उसी पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ है, जो विश्व का महानतम उपन्यास माना जाता है। उस से पहले 13–15 वीं सदी में मंगोल और तातार हमलावरों ने रयाजान, सुजदल, मॉस्को, त्वेर, कीव, रोस्तोव, आदि कितने ही रूसी नगरों का पूर्ण विनाश कर दिया था! मंगोलों ने रूस पर दो सदियों तक, 15वीं सदी के अंतिम चरण तक शासन किया। अंततरू हारने के बाद भी मंगोल हमलावर क्रीमिया पर छापे मारते रहते थे। उन्होंने भी दो बार मास्को को जला डाला था और 16वीं सदी तक रूसियों को गुलाम बनाकर सीरिया, फारस और तुर्की बाजारों में बेचा। इसलिए, रूसी मानस में दोनेत्स्क, क्रीमिया, आदि केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। वह विदेशी हमलों, भयावह उत्पीड़न झेलने और लड़ने का ऐतिहासिक प्रतीक भी है। न केवल क्रीमिया रूस का ऐतिहासिक अंग है, बल्कि स्वयं उक्रेनी लोग भी श्छोटे रूसीत्र कहे जाते रहे हैं। पहले सदियों तक रूस का नाम ही श्कीव–रूसत्र था। पूरा उक्रेन ही रूस का अंग था। उसे सोवियत संघ का एक अलग प्रांत भी रूसी नेता लेनिन ने 1919 में बनाया। उस से पहले उक्रेन कभी रूस से अलग देश तो क्या, अलग प्रांत भी नहीं रहा था। अतरू रूस–उक्रेन युद्ध भाइयों की लड़ाई है। चाहे दोनों के चरित्र में अब काफी अंतर क्यों न आ गया हो। अतरू, ऐतिहासिक रूप से रूसियों के लिए युद्ध उन के अस्तित्व का सामान्य अंग रहा है। रूसी सैन्य अकादमी के प्रमुख रहे निकोलाई सुखोतिन ने उन्नीसवीं सदी के अंत में हिसाब लगाकर बताया था कि उस से पिछली पाँच सदियों में रूस का लगभग दो तिहाई समय युद्ध लड़ते बीता है। उस के बाद, आगे बीसवीं सदी का हिसाब तो ऊपर देख ही चुके हैं। इसीलिए, रूसी समाज अपने सैनिकों और स्मारकों के प्रति जो विशेष और नियमित आदर स्थान रखता है, वह विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है। मॉस्को में विवाह के बाद नवविवाहित जोड़ा सब से पहले श्अनाम सैनिक के स्मारकत्र पर जाकर फूल चढ़ाता है। हिटलर पर जीत का दिन, 9 मई रूस में सब से बड़े राष्ट्रीय पर्व जैसा है, जिस में सभी रूसी समान श्रद्धा रखते हैं। ऐसा संभवतरू दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अनेक रूसी योद्धाओं को संत की उपाधि दी है। इसलिए नहीं कि उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च को फैलाया या उस के मिशनरी थे, जैसा कैथोलिक चर्च परंपरा में है। बल्कि इसलिए कि उन रूसी योद्धाओं ने समाज की रक्षा की। दमित्री दोन्सकी, अलेक्जेंडर नेवस्की, और एडमिरल उसाकोव ऐसे कुछ ऐतिहासिक रूसी योद्धा रहे हैं, जिन्होंने मंगोलों, ट्यूटनों, या तुर्कों से लड़ कर मातृभूमि को मुक्त कराया, या उस की रक्षा की थी। उन्हें रूसी चर्च ने संत की उपाधियाँ दी। यह भी दुनिया में अपवाद है, कि सैनिक योद्धाओं को श्संतत्र की उपाधि मिली। इसीलिए, रूसियों की भावना, संस्कृति और प्रतिक्रिया को अन्य देशों के सांस्कृतिक पैमाने से देखना भूल है। वैसे भी, भिन्न–भिन्न संस्कृतियाँ अपने कुछ विशिष्ट मानदंड रखती हैं। रूसियों पर तो यह और भी अधिक लागू है। जर्मन–अमेरिकी राजनीति शास्त्री हान्स मार्गेन्थाऊ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक श्पॉलिटिक्स एमंग नेशंसत्र (1948) में श्राष्ट्रीय चरित्रत्र पर एक विस्तृत और बड़ा रोचक अध्याय लिखा है। उस में, सौ सालों के अंतराल में रूसी चरित्र के दो अनोखे विवरण हैं। एक में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बर्लिन में एक रूसी सैनिक की दयालुता और दृढ़ता एक ही घटना में इकट्ठे दिखाई गयी है। तब बर्लिन रूसी फौज के अधिकार में आ चुका था। वह वास्तविक घटना इस प्रकार हैरूद्द कोई रूसी सैनिक बारह जर्मन बंदियों को लाइन में लगाकर लिए जा रहे हैं। एकाएक नागरिकों में एक युवती चीख कर बंदियों में अपने पतिध्प्रेमी को पहचान लेती है। वह दौड़ कर आकर उस से लिपट जाती है। रूसी सैनिक उसे रोकता है। आस–पास के जर्मन लोग सकते में आ जाते हैं।

उत्तरी विस में घट गए सबसे ज्यादा 1.91 लाख मतदाता

लखनऊ, (संवाददाता)। एसआईआर प्रक्रिया के बाद जिला प्रशासन ने जो मसौदा मतदाता सूची जारी की है उसमें जिले में 12 लाख से अधिक मतदाता कम हो गए हैं। जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 1.91 लाख मतदाताओं का नाम कटे हैं। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 60 हजार मतदाता घटे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया से पहले जिले में 39,94,535 मतदाता थे। अब इनकी संख्या घटकर 27,94,397 रह गई है। इस प्रकार एसआईआर के बाद जिले में 12,00,138 मतदाता कम हुए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचक नामावली के मसौदा प्रारूप का प्रकाशन किया गया। इस पर छह फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। दावों एवं आपत्तियों की जांच, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 27 फरवरी तक पूरी की जाएगी। अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन छह मार्च को होगा। सहायता करेंगे बीएलओरू जिला

निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने बताया कि एसआईआर के दूसरे चरण में जिले के सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में 1,556 मतदान केंद्रों और 4,132 मतदेय स्थलों पर बीएलओ एवं निर्वाचन कर्मी उपस्थित रहकर मतदाताओं की सहायता करेंगे। नए मतदाता अपना नाम जोड़ने, नाम में संशोधन व नाम हटाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म वेबसाइट अवजमत.मबप.हवअ. पद पर या निर्धारित तिथियों पर संबंधित मतदेय स्थलों पर ऑफलाइन प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं। 89 थर्ड जेंडर मतदाता एसआईआर प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची में थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 89 मिली है। लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सबसे अधिक 15 थर्डजेंडर मतदाता हैं। मलिहाबाद, बक्शी का तालाब व लखनऊ कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र में नौ–नौ, सरोजनीनगर व लखनऊ उत्तर क्षेत्र में 14–14, मोहनलालगंज क्षेत्र में 11, लखनऊ मध्य क्षेत्र में पांच व लखनऊ पूर्व क्षेत्र में तीन थर्ड जेंडर मतदाता हैं। एसआईआर प्रक्रिया के बाद मंगलवार जो मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई है उसके मुताबिक जिले की सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 1,91,496 महिला मतदाता हैं, जबकि मोहनलालगंज (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 1,36,044 महिला मतदाता हैं। मतदाता सूची के मुताबिक मलिहाबाद में 1,37,427, बक्शी का तालाब विस क्षेत्र में 1,79,796, लखनऊ पश्चिम क्षेत्र में 1,53,582, लखनऊ उत्तर क्षेत्र में 1,45,598, लखनऊ पूर्व क्षेत्र में 1,42,408, लखनऊ मध्य क्षेत्र में 1,16,623 और लखनऊ कैंटोनमेंट क्षेत्र में 1,07,263 महिला मतदाता हैं।

फेरी दुकानदार की झोपड़ी में लगी आग

लखनऊ, (संवाददाता)। पचौरी गांव में मंगलवार सुबह फेरी दुकानदार की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में आकर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। समय रहते परिवार के सभी सदस्य झोपड़ी से बाहर आ गए, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पचौरी गांव के सूरज गांव–गांव फेरी लगाकर रेडीमेड कपड़े बेचते हैं। सूरज के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब पांच बजे वह पिता बेचालाल, मां विशुनदेई और बहन पूनम के साथ टिनशेड की झोपड़ी में सो रहे थे। अचानक वहां आग लग गई। परिवार के लोग शोर मचाते हुए बाहर निकल आए। आसपास के ग्रामीणों की मदद से बाल्टी और सबमर्सिबल पंप के जरिये पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। टिनशेड के नीचे रखा रेडीमेड कपड़े, अनाज और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। ग्राम प्रधान नीता यादव की सूचना पर पहुंचे लेखपाल ने नुकसान का आकलन कर तहसील प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। सूरज ने आग की घटना में साजिश की आशंका जताई है। एसडीएम पवन पटेल ने बताया कि घटना में गृहस्थी का सामान जलने से आर्थिक नुकसान हुआ है। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवार की यथासंभव सहायता की जाएगी। हुलास खेड़ा चौकी इंचार्ज अनूप सिंह के मुताबिक आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। जांच की जा रही है। दुकानदार ने तहरीर नहीं दी है।

संक्षिप्त खबरें

चीफ इंजीनियर के घर के पोर्च में लगी आग, दो कारें व बाइक जली

लखनऊ, (संवाददाता)। आशियाना के सेक्टर–के में मंगलवार शाम 6रू30 बजे विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह आवास के पीछे मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर प्रत्यूष दीक्षित के घर के पोर्च में आग लगने से वहां खड़ी दो कारें व हार्ले डेविडसन बाइक जल गई। सूचना पर पहुंची आलमबाग फायर स्टेशन की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रत्यूष दीक्षित वर्तमान में चेन्नई में कार्यरत हैं। घर पर उनकी पत्नी सोनल और दो बच्चों थे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मंगेश कुमार का कहना था कि संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। कोई जनहानि नहीं हुई है।

कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में पीईटी स्कैन जांच की मशीन लगी

लखनऊ, (संवाददाता)। कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान में पीईटी स्कैन जांच की मशीन लग गई है। निदेशक प्रो. एमएलबी भट्ट ने बताया कि संस्थान में यह जांच करीब 11 हजार रुपये में होगी। निजी केंद्र पर इसकी फीस 20 हजार रुपये के करीब है। संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वरुण विजय ने बताया कि डिजिटल पेट सीटी स्कैनर से कैंसर रोगियों में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के प्रति रोग की प्रतिक्रिया का आकलन ज्यादा सटीक और प्रभावी ढंग से किया जाता है। अभी तक संस्थान में इस जांच की सुविधा न होने से मरीजों को निजी केंद्रों पर भेजा जाता था। पेट स्कैन जांच के लिए आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए फीस 10,450 रुपये रखी गई है। अन्य योजनाओं के लिए फीस करीब 11 हजार रुपये है। मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से डॉ. आरएस यादव के साथ संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विजेंद्र कुमार और न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता उपस्थित रहे।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर नगर निगम का कड़ा प्रहार

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम लखनऊ ने शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में सख्ती दिखाते हुए मंगलवार को जोन–7 क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर संचालित इस अभियान का उद्देश्य प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग पर प्रभावी रोक लगाना और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा।नगर आयुक्त के निर्देशों के क्रम में जोनल सेनेटरी अधिकारी अजीत कुमार राय के नेतृत्व में पॉलीटेक्निक चौराहा, चिनहट तिराहा और अयोध्या मार्ग के आसपास विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग व भंडारण की गहन जांच की गई। अभियान में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक रूपेन्द्र भास्कर, बृजेश प्रजापति, संचिता मिश्रा, लखनऊ स्वच्छता अभियान प्रा. लि. की टीम, प्रवर्तन दल (296) और एटीएफ टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की।जांच के दौरान गुप्ता कचौड़ी भंडार, काफी अड्डा, शहीद कॉम्प्लेक्स, अल नवाज मुरादाबादी बिरयानी, रॉयल जनरल स्टोर और लखनऊ नवाबी सहित कई प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पाया गया।

थाईलैंड में बैठकर बुजुर्ग को रखा डिजिटल अरेस्ट, चार गुर्गे गिरफ्तार... 54.60 लाख रुपये ठगे थे

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ में गोमतीनगर के रहने वाले वरिष्ठ नागरिक राजेंद्र प्रकाश वर्मा को थाईलैंड में मौजूद जालसाज व उसके गैंग के लोगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 54.60 लाख रुपये ठगे थे। इस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने मंगलवार को चार जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी म्यूल खातों में ठगी की रकम मंगवाते थे और क्रिप्टो करेंसी के जरिये विदेश भेजते थे। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि 13 दिसंबर को राजेंद्र प्रकाश को एनआईए और एटीएस अधिकारी बताकर जालसाजों ने आतंकियों को फंडिंग का आरोप लगाते हुए उन्हें धमकाया। आरोपियों ने जांच के नाम पर राजेंद्र प्रकाश को सात दिन तक डिजिटल अरेस्ट रख इंडसइंड और बीओबी के दो खातों में 54.60 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे। राजेंद्र ने 19 दिसंबर को साइबर क्राइम थाने में दो जालसाजों रंजीत कुमार और प्रेम कुमार गौतम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दोनों के मोबाइल नंबर भी पीड़ित ने दिए थे। साइबर क्राइम सेल की टीम ने जांच शुरू की तो पता चला कि ठगी की रकम म्यूल खातों में जमा करवाई गई है। इन खातों से ठगी की रकम को निकाल भी लिया गया था। सर्विलांस और बैंक से मिली डिटेल की मदद से मंगलवार को साइबर क्राइम सेल की टीम ने चार जालसाजों वजीरगंज निवासी मो. सुफियान, दुबग्गा निवासी मो. आजम, गुडंबा निवासी आरिफ इकबाल और मदेयगंज निवासी उजैर खान को गिरफ्तार किया। गिरोह में 12 लोग शामिलरू डीसीपी ने बताया कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाला सरगना थाईलैंड में मौजूद है। पकड़े गए आरोपी ठगी की रकम को म्यूल खातों में मंगवाते थे और उसे विदेश में बैठे सरगना को कमीशन काटकर क्रिप्टो करेंसी में भेज देते थे। गैंग में 12 लोग शामिल हैं। कुछ बहराइच व श्रावस्ती के रहने वाले हैं। उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। म्यूल खाताधारकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस को आरोपियों के पास से पांच मोबाइल फोन, 25234 रुपये, पांच डेबिट कार्ड, एक पैन व आधार कार्ड मिला। आरोपी सुफियान सबमर्सिबल का काम और आजम प्रॉपर्टी डीलिंग करता है। आरिफ खुद को समाचार पत्र से जुड़ा बताता है, उजैर नीट की तैयारी कर रहा है। उजैर मूलरूप से बहराइच के कैसरगंज प्यारेपुर का निवासी है। म्यूल खाते का प्रयोग असली खाताधारक के बजाय साइबर जालसाज करते हैं। रुपये का लालच देकर कम पढ़े–लिखे और कमजोर वर्ग के लोगों के दस्तावेज लेकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाए जात हैं।

धान क्रय केंद्रों पर खरीद ठप, बिचौलियों की मौज

लखनऊ, (संवाददाता)। किसानों से सीधे धान खरीद के लिए खोले गए सरकारी क्रय केंद्रों पर तौल न होने से किसान भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। केंद्र प्रभारियों का कहना है कि पहले से खरीदे गए धान की मिलें उठान नहीं कर रही हैं, जिससे बोरों और भंडारण की जगह की कमी हो गई है। इस स्थिति में किसान अपनी उपज औने–पौने दामों पर बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से पीसीएफ के माध्यम से नगराम क्षेत्र में सहकारी समिति इस्माइलनगर, काटा करौंदी, नगराम दक्षिण, गढ़ा, देवती और समेसी में धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। वर्तमान में सभी केंद्रों पर धान खरीद लगभग ठप पड़ी है। सिरौना निवासी राजकुमार पांडे, रामपुर के राम मिलन, ममईमऊ के रामफेर, हुसैनाबाद के मनमोहन और घोड़सारा के शैलेन्द्र ने बताया कि उनका पंजीकरण फार्म इस्माइल नगर क्रय केंद्र पर काफी समय से जमा है, लेकिन रोज चक्कर लगाने के बावजूद धान की तौल नहीं हो पा रही है। यही स्थिति गढ़ा, नगराम दक्षिण और देवती केंद्रों की भी है। नगराम दक्षिण केंद्र प्रभारी फूलचंद ने बताया कि नवंबर से शुरू हुई खरीद में अब तक 103 किसानों से 3100 क्विंटल धान खरीदा गया है। इस्माइल नगर केंद्र प्रभारी संजय वर्मा के अनुसार अब तक 98 किसानों से 3400 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है, जबकि आठ किसानों से लगभग 400 क्विंटल धान की खरीद अभी शेष है। पहले से खरीदा गया धान मिलर द्वारा न उठाए जाने के कारण जगह और बोरों की कमी से आगे की खरीद संभव नहीं हो पा रही है। गढ़ा और देवती केंद्रों पर भी यही स्थिति है। यहां केंद्र प्रभारी हरिश्चंद्र और सतीश ने बताया कि लगभग 15–15 किसानों से 1000–1000 क्विंटल धान की तौल अभी बाकी है। अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल सका है। खरीदा गया धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है, जिससे बारिश में खराब होने का खतरा बना हुआ है।

संक्षिप्त खबरें

पंचायती राज विभाग ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष कैलेंडर जारी किया

लखनऊ, (संवाददाता)। महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्राम पंचायतों में उनकी वास्तविक एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर आधारित विशेष कैलेंडर जारी किया है। यह कैलेंडर केवल तिथियों का संकलन नहीं है, बल्कि पंचायतों में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में तैयार किया गया है। कैलेंडर के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि ग्राम पंचायतों में महिलाएं केवल नाममात्र की प्रधान या प्रतिनिधि न बनें, बल्कि विकास कार्यों और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो। इस पहल से महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने, अपनी बात मजबूती से रखने और पंचायत संचालन में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाएगा।यह कैलेंडर ग्राम पंचायतों, पंचायत भवनों और विभागीय कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों में महिलाओं की सहभागिता को लेकर सकारात्मक सोच विकसित हो सके।माननीय पंचायती राज मंत्री श्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि नारी शक्ति की नई उड़ान, गांव बदल रही महिला प्रधान केवल एक पहल नहीं, बल्कि मजबूत लोकतंत्र की नींव है। जब पंचायतों में महिलाएं सशक्त होंगी और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएंगी, तभी गांवों का समग्र विकास संभव होगा। उन्होंने कहा कि यह कैलेंडर महिला हितैषी सोच को जन–जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा।

उत्तर प्रदेश को कृषि अवसंरचना निधि योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का सम्मान

लखनऊ, (संवाददाता)। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की रीजनल कांफ्रेंस समारोह में उत्तर प्रदेश को "बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट" का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्रीमती अर्चना रॉय, प्रभारी एआईएफध्एसपीएमयू, को "बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय" का प्रशस्ति पत्र भी दिया गया।यह जानकारी मा० सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जे.पी.एस. राठौर ने दी। उन्होंने बताया कि कृषि अवसंरचना निधि योजना का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 13,384 प्रोजेक्ट्स के लिए 8,394.17 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 12,602 लाभार्थियों को 5,754.37 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने अगस्त 2020 से कृषि अवसंरचना निधि योजना प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य फसलोपरांत हानियों को कम करना और कृषि अवस्थापना के विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज उपादान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज उपादान कृषि उद्यमियों, एफपीओ, पैक्स, मंडी समितियों और राज्य एजेंसियों (जैसे एफसीआई, एसडब्ल्यूसी, पीसीएफ, सीडब्ल्यूसी) को उपलब्ध कराया जाता है।

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने पास की आत्मनिर्भरता की परीक्षा

लखनऊ, (संवाददाता)। डॉ. शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय ने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव किया है। विश्वविद्यालय में पहली बार बिना सह–लेखक के सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें दो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने तकनीक के सहारे स्वयं उत्तर लिखे। बीए पांचवें सेमेस्टर की छात्रा श्वेता आंचल और छात्र सुयश पांडेय ने अपने–अपने लैपटॉप के माध्यम से परीक्षा दी। प्रश्नपत्र यूएसबी ड्राइव में उपलब्ध कराए गए, जिससे परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुलभ, पारदर्शी और स्वायत्त बनाया गया। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों ने स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और हेडफोन की मदद से प्रश्न सुने और की–बोर्ड के जरिये अपने उत्तर स्वयं टाइप किए। इस प्रक्रिया में किसी सह–लेखक की जरूरत नहीं पड़ी। इससे परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता के साथ–साथ विद्यार्थियों की आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित हुई। इस पहल से पहले दोनों विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में छह माह तक विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कंप्यूटर संचालन, स्क्रीन रीडर का उपयोग, की–बोर्ड दक्षता और परीक्षा–उन्मुख तकनीकी अभ्यास शामिल रहा। प्रशिक्षण के कारण विद्यार्थी परीक्षा के दौरान पूरी तरह सहज नजर आए। अब तक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सह–लेखक रखना पड़ता था, जिस पर पूरी परीक्षा अवधि में पांच से दस हजार रुपये तक का खर्च आता था। स्क्राइब–फ्री व्यवस्था से यह आर्थिक बोझ भी खत्म होगा। वेता आंचल ने कहा, विश्वविद्यालय में मिले प्रशिक्षण से आत्मविश्वास बढ़ा। पहली बार पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने उत्तर लिख पाई। यह अनुभव सशक्तिकरण जैसा है। सुयश पांडेय ने कहा, लगातार अभ्यास के कारण लैपटॉप का उपयोग आसान हो गया। परीक्षा में किसी पर निर्भर न रहना हमारे लिए सम्मान की बात है। कुलपति आचार्य संजय सिंह के अनुसार यह पहल दिव्यांग विद्यार्थियों को समान अवसर देने की दिशा में ठोस कदम है। स्क्राइब–फ्री परीक्षा से विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता का निष्पक्ष मूल्यांकन संभव होगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर 'डिजिटल अरेस्ट' की साजिश का भंडाफोड

लखनऊ, (संवाददाता)। साइबर क्राइम पुलिस थाना कमिश्नरेट लखनऊ ने फर्जी पुलिस और छप्।६।ॐ अधिकारी बनकर लोगों को 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर डराने वाले संगठित साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह एक सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर से 54 लाख 60 हजार रुपये की ठगी कर चुका था। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से नकदी, कई मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पैन व आधार कार्ड, प्रेस आईडी कार्ड और चेक बरामद किए गए हैं।साइबर क्राइम पुलिस के अनुसार पीड़ित राजेन्द्र प्रकाश वर्मा को 13 दिसंबर 2025 को साइबर ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क किया। कॉल करने वालों ने खुद को पुलिस इंस्पेक्टर और छप्।६।ॐ अधिकारी बताकर उन पर आतंकी फंडिंग और फर्जी बैंक खातों के जरिए करीब सात करोड़ रुपये के अवैध लेन–देन का झूठा आरोप लगाया। इसके बाद पीड़ित को 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर मानसिक दबाव में रखा गया और लगातार ऑनलाइन निगरानी में होने का डर दिखाया गया। जांच और वेरिफिकेशन के बहाने डराकर पीड़ित के एसबीआई खाते से दो अलग–अलग बैंक खातों में कुल 54 लाख 60 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। भय और मानसिक तनाव के कारण पीड़ित ने यह राशि स्थानांतरित कर दी।मामले में साइबर क्राइम थाना लखनऊ में अपराध संख्या 207ध2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के अनावरण के लिए पुलिस आयुक्त लखनऊ और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई, जिसने तकनीकी साक्ष्यों और बैंक ट्रांजेक्शन के आधार पर गिरोह का पता लगाते हुए मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे। गिरोह के कुछ सदस्य फर्जी पुलिस या केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते थे।

पदोन्नति सहित 17 सूत्रीय मांगों पर अमल न होने पर हड़ताल की चेतावनी

लखनऊ, (संवाददाता)। निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय पर मंगलवार को यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना–प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शासन स्तर पर लंबित 18 प्रकरणों और निदेशालय स्तर पर पदोन्नति सहित 17 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र निर्णय की मांग की। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी दी गई। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विवेक यादव ने कहा कि जिला और मंडल स्तर पर किए गए प्रदर्शन के बावजूद विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसे में कर्मचारियों को मजबूरन निदेशालय स्तर पर धरना देना पड़ रहा है। प्रांतीय उपाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वैयक्तिक सहायक ग्रेड–एक एवं ग्रेड–दो के पदों पर पदोन्नति आदेश जारी करने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। मंडल और जिला स्तर पर पद सृजित नहीं किए गए हैं, जबकि कर्मचारियों से संबद्ध कर कार्य लिया जा रहा है। इसके अलावा राजकीय सेवाओं को पेंशन सेवा में न जोड़कर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो 12 जनवरी को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), 19 जनवरी को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय तथा 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और विभाग के उच्चाधिकारियों की होगी। धरने में बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

लखनऊ में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम का बड़ा एक्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम लखनऊ ने शहर में लगातार बढ़ते अवैध अतिक्रमण और उससे उत्पन्न हो रही यातायात बाधाओं को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को व्यापक और बहुस्तरीय प्रवर्तन अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर संचालित इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य प्रमुख सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कर आम नागरिकों को सुगम, सुरक्षित और निर्बाध यातायात सुविधा उपलब्ध कराना रहा। नगर निगम की विभिन्न जोनल टीमों ने पुलिस बल के सहयोग से शहर के कई क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई कर अवैध ठेलों, गुमटियों, काउंटरों और अन्य अस्थायी ढांचों को हटाया।जोन–03 क्षेत्र में जोनल अधिकारी आकाश कुमार के निर्देशन में प्रवर्तन दल (296) द्वारा सी–25 से पार्क महानगर तक अतिक्रमण के विरुद्ध सघन कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए दो फल एवं सब्जी के ठेले और चार चाय के ठेले हटाए गए। साथ ही चार लोहे के काउंटर और एक छोटा छतदान युक्त लोहे का ठेला जब्त किया गया। अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी भी दी गई।इसी क्रम में जोन–05 क्षेत्र के अंतर्गत एयरपोर्ट नादरगंज चौराहे से पटरी दरोगा खेड़ा तक और सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र में अस्थायी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में पांच ठेले, तीन गुमटी और दो काउंटर हटाए गए, जबकि दो काउंटर जब्त किए गए। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के मामलों में 500 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। इसके अतिरिक्त गंदगी फैलाने और पॉलीथीन के उपयोग से संबंधित मामलों में 2000 रुपये का शमन शुल्क भी वसूला गया। यह अभियान जोनल अधिकारी विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में कर अधीक्षक सभाजीत सिंह, जोनल सेनेटरी अधिकारी सचिन सक्सेना, राजस्व निरीक्षक पियूष तिवारी, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक सुभाष चौधरी, प्रवर्तन दल और पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा संचालित किया गया।वहीं जोन–08 क्षेत्र में भी अवैध अस्थायी अतिक्रमण, होल्डिंग, बैनर और पोस्टरों के विरुद्ध वृहद अभियान चलाया गया। जोनल अधिकारी विकास सिंह के निर्देशन में मेदांता हॉस्पिटल और जी–20 चौराहे के आसपास अवैध रूप से लगाए गए।

जौनपुर में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा जारी,तापमान में गिरावट पारा पहुंचा 7 डिग्री

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ

है। बढ़ती शीतलहर के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों और मदरसों में 8 तथा 9 जनवरी को शीतकालीन अवकाश घोषित किया है।जिले में गुरुवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दिन आर्द्रता 88 प्रतिशत, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 188 और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे रही। बुधवार को आर्द्रता 87 प्रतिशत और ।फप 125 था, जबकि हवाएं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं और दृश्यता 50 मीटर तक कम हो गई थी। तेज हवाओं और ठंड के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही धीमी रही। रात में घने कोहरे से बसों और ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ, जिससे सड़कें सुनसान रहीं। राज्य मौसम केंद्र के प्रभारी अतुल कुमार ने बताया कि तापमान में गिरावट के कारण प्रदेश के कई जिले ठंड की चपेट में हैं। उन्होंने आसमान में बादल छाए रहने और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना जताई है। कड़ाके की ठंड से किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें फसलों की सिंचाई करने और पशुओं की देख–रेख में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। घने के कोहरे के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है।लोगो का कहना है कि ठंड इतनी ज्यादा है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है।खास कर बुजुर्गों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। वही इस मामले में बच्चों के विशेषज्ञ डॉ अभिषेक मिश्रा का कहना है कि इस ठंड में 1 से 10 साल तक के बच्चों को विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसका सीधा असर बच्चों के स्वस्थ पर पड़ेगा बच्चों को सांस लेने में उनके पाचन में मांसपेशियों में अकड़ना और दर्द हो जाता है।

गुरुक्षेत्र फाउंडेशन के तत्वावधान में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर गुरुक्षेत्र फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस जनकल्याणकारी कार्यक्रम का संचालन संस्था के संरक्षक इंद्रदमन उपाध्याय जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में तथा संस्था अध्यक्ष विमलेश उपाध्याय जी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 50 से अधिक वृद्धजन, निराश्रित एवं आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष–महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। भीषण शीतलहर के मध्य कंबल प्राप्त कर लाभार्थियों के चेहरों पर संतोष एवं राहत की स्पष्ट झलक देखने को मिली, जो इस मानवीय प्रयास की सार्थकता को दर्शाता है। इस अवसर पर सुभाष उपाध्याय (पूर्व प्रधान), रामराज सिंह जी (पूर्व प्रधान), लाल प्रताप सिंह , गोरखनाथ उपाध्याय , शक्ति उपाध्याय सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे एवं सभी ने इस जनसेवा पहल की भूरि–भूरि प्रशंसा की। कार्यक्रम के समापन पर संस्था की ओर से उपस्थित समस्त अतिथियों, जनप्रतिनिधियों एवं सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया। यह आयोजन सामाजिक सरोकार, मानवीय संवेदना एवं जनकल्याण की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल सिद्ध हुआ।

संक्षिप्त खबरें

सद्भावना क्लब जौनपुर का चुनाव संपन्न, विवेकानंद मौर्य अध्यक्ष चुने गए

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सद्भावना क्लब जौनपुर का वार्षिक चुनाव बुधवार शाम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव में विवेकानंद मौर्य को 31वाँ अध्यक्ष चुना गया। चुनाव में हर्ष माहेश्वरी को सचिव, विनीत गुप्ता को कोषाध्यक्ष, हाजी सैयद फरोग अहमद को सह सचिव तथा रविकांत जायसवाल को सह कोषाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष डॉ. एम.पी. बरनवाल ने नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संस्था का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि सद्भावना क्लब एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए निरंतर कार्य करती आ रही है और आगे भी इसी भावना से कार्य करती रहेगी। पूर्व अध्यक्ष डॉ. अलमदार नजर, श्रवण साहू, नरसिंह अवतार जायसवाल एवं हफीज शाह ने भी अध्यक्ष एवं सभी नवचयनित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। चुनाव अधिकारी एवं पूर्व अध्यक्ष मधुसूदन बैंकर्स ने शांतिपूर्ण एवं सकुशल चुनाव संपन्न कराया। कार्यक्रम का संचालन सचिव विनीत गुप्ता ने किया। अंत में अध्यक्ष मोहम्मद रजा खान ने उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संतोष अग्रहरि, श्रीमती आदर्श वर्मा, विजय अग्रवाल,अतीत मौर्य, विकास अग्रहरि, मोहित मौर्य, अखिलेश अग्रहरि, अमित साहू, असगर मेहंदी खान, नागेंद्र यादव राज कॉलेज,शोएब कलाम, राहुल साहू, डॉ. राशीद खान,सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

जनपद न्यायालय, जौनपुर में निम्नलिखित तिथियों को अवकाश घोषित किया गया हैरूजनपद न्यायाधीश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार शशि ने अवगत कराया है कि जनपद जौनपुर के न्यायालयों में वर्ष 2026 के दौरान अवकाश एवं कार्य दिवसों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। उन्होने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम में जनपद न्यायालय, जौनपुर में निम्नलिखित तिथियों को अवकाश घोषित किया गया है। 14 जनवरी 2026 (बुधवार) मकर संक्रांति, 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) अलविदा जुम्मा, 25 मार्च 2026 (बुधवार) अष्टमी, 17 सितम्बर 2026 (गुरुवार) विश्वकर्मा पूजा, 24 नवम्बर 2026 (मंगलवार) कार्तिक पूर्णिमाधगुरु नानक जयंती। इसके अतिरिक्त, न्यायालय अधिवक्ता संघ द्वारा प्रस्तावित अवकाश के अनुसार 15 फरवरी 2026 (रविवार) के एवज में 10 नवम्बर 2026 को भइया दूज के अवसर पर अवकाश, 08 नवम्बर 2026 (रविवार) के एवज में दिनांक 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को रक्षा बन्धन के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है।

रामनगरी को दो सुलभ शौचालय महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने किया समर्पित

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने लोकार्पण के साथ रामनगरी को दो सुलभ शौचालय समर्पित किया। रामपथ पर स्थित सरदार गणपति राय सरस्वती विद्या मंदिर परिसर के भीतर और बाहर शौचायलयों का निर्माण टाइनी टाट्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सहयोग से किया गया है। इसका संचालन टाइनी टाट्स ग्रुप आफ स्कूल एवं अयोध्या विकास प्राधिकरण करेगा।महापौर ने बताया कि शौचालय पांच–पांच सीटर है।एक का प्रयोग विद्यालय के छात्र करेंगें, जबकि दूसरे का लाभ अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा।महापौर ने फीता काटकर उद्घाटन करने के पूर्व विद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में कहा कि अयोध्या अवसर की संभावना वाला महानगर बन कर उभरा है, क्योंकि यहां देश और दुनिया से प्रतिमाह लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी है कि वह नगर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें।उन्होंने नगर निगम द्वारा किए जा रहे सफाई कार्य की विस्तार से चर्चा की और बताया कि नागरिक समितियों के माध्यम से पांच वार्डो की सफाई का कार्य कराया जा रहा है।महापौर ने सरयू नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किया जा रहे उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की।उन्होंने नागरिकों एवं विभिन्न संस्थानों से वार्डों को गोद लेकर स्वच्छता के कार्य में सहयोग करने का आह्वान किया।टाइनी टाट्स की निदेशक बिन्नी सिंह ने पर्यावरण संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की।उन्होंने फलदार पेड़ लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ पक्षियों के भोजन का भी प्रबंधा होगा।उन्होंने बच्चों को सामुदायिक कार्यों से जोड़ने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे नई पीढ़ी में अनुशासन बढ़ेगा और वह नशे जैसी कुप्रवृत्ति से बचेंगे।इस मौके पर साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दानपति तिवारी, विद्या मंदिर के प्रबंधक प्रमोदकांत, पार्षद अनिकेत यादव एवं राजकरण, पूर्व सभासद रमाकांत विश्वकर्मा, सरदार रणजीत सिंह, गुनीत औलख, प्रधानाचार्य मुकेश चंद्र शर्मा एवं मुक्ति श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।कार्यक्रम का संचालन एकता भूटानी एवं वंदना सिंह ने किया।

जनता दर्शन में आई समस्याओं के निराकरण के लिए डीएम ने दूर करने के दिये अधिकारियों को निर्देश

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या। डीएम निखिल टीकाराम फुंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनता दर्शन का आयोजन किया गया।जिसमें जिले के विभिन्न ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों से आए आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कीं।जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि जनता की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए तथा शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न हो। जनता दर्शन में मुख्य रूप से भूमि विवाद, राजस्व संबंधित प्रकरण, पेंशन, विद्युत, जलापूर्ति, सड़क मरम्मत, स्वास्थ्य सुविधा तथा जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दे सामने आए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक मामले की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए और शिकायतकर्ता को निस्तारण की जानकारी समय से उपलब्ध कराई जाए।

संक्षिप्त खबरें

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मे डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय की स्नातक एवं परास्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा शुरू

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डॉ. राममनोहर लोहिया अवधा विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में स्नातक एवं परास्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज 8 जनवरी से शुरू हो गई।परीक्षा को तीन पालियों में संपन्न कराया जा रहा है।प्रथम पाली सुबह 8रू30 से 10रू30 बजे तक द्वितीय पाली 9रू00 बजे से 12रू00 बजे तक हम तृतीय पाली 2रू00 बजे से 5रू00 बजे तक निर्धारित की गई है।इस संबंध मे कुलपति कर्नल डॉ. बिजेंद्र सिंह के निर्देश के क्रम में सभी केंद्रों को नकलविहीन, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए छात्र–छात्राओं को मिक्सड सीटिंग प्लान तैयार कर उन्हें अलग–अलग विषयों के साथ बैठने का निर्देश दिया गया है।नकल विहीन परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित सचल दलों को सक्रिय कर परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है।वही परीक्षा नियंत्रक विनय कुमार सिंह ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापक एवं प्राचार्य को निर्देशित किया गया है।उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी निर्देश के क्रम में सभी परीक्षा केंद्रों को विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित सीसीटीवी कंट्रोल रूम से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। नवीन परिसर केंद्र व्यवस्थापक डॉ. विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि परीक्षाएं सुचारू रूप से केंद्र पर शुरू हो गई है।पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के छात्र–छात्राओं को बैठने के लिए निर्देशित सीटिंग प्लान तैयार किया गया है और सघन तलाशी भी कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से संबंधित फार्म ऑनलाइन ही होंगे स्वीकृत – अश्वनी तिवारी

अयोध्या। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना मुख्यमन्त्री बाल सेवा योजना (सामान्य) को अब ऑनलाइन कर दिया गया है।अब ऑफ लाइन फार्म अब जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यह जानकारी जिला प्रोविजनल अधिकारी अश्वनी कुमार तिवारी ने दिया उन्होंने बताया कि आवेदकों की सुविधा के लिए वह किसी भी जनसेवा केन्द्र से आवेदन वेबसाइट www-mbsyup-in पर ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी वेबसाइट से या फिर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सम्पर्क कर सकते हैं।बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक व बच्चे की संयुक्त फोटो अपलोड होना,आवेदक व बच्चे का आधार कार्ड, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र,आवेदक का आय प्रमाण पत्र,आवेदक का जाति व निवास प्रमाण पत्र,बच्चे का डी०बी०टी० इनेबल्ड खाता संख्या पासबुक अपलोड, आवेदक का मोबाइल नम्बर,बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, वही 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों का विद्यालय द्वारा जारी अध्ययन प्रमाण पत्रध्अपार आइ०डी० (पेन नम्बर),सभी आवेदन–पत्र सम्बन्धित उपजिलाधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन आई०डी० पर होने चाहिए। बताया कि इन सभी कागजातों का सत्यापन होने के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी की लॉगिन पर अग्रसारित किये जायेंगे, जिसके उपरान्त अनुमोदन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की फांसी लगाकर मौत ,परिजन लगा रहे दहेज के लिया हत्या का आरोप

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में चंदवक थाना क्षेत्र के हीरापुर मचहटी गांव में बुधवार रात एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान अफसाना के रूप में हुई है, जिसकी शादी 10 नवंबर 2018 को सलमान पुत्र अजीम निवासी हीरापुर मचहटी से हुई थी।घटना की जानकारी गुरुवार सुबह हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतका के परिजनों को सूचित किया।मौके पर पहुंचे मृतका अफसाना के पिता सलामुद्दीन, जो सिहौली, थाना केराकत के निवासी हैं, ने चंदवक थाने में लिखित तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शादी के समय से ही दहेज को लेकर विवाद चल रहा था। सलामुद्दीन के अनुसार, सलमान (पति), आजाद ,अरमान, करिया, (देवर) (पुत्रगण अजीम), अजीम (पुत्र फेकू) और तमन्ना (पत्नी आजाद) अफसाना पत्नी अजीम लगातार चार पहिया वाहन, दो लाख रुपये नकद और एक सिकड़ी (चेन) की मांग कर रहे थे। पिता ने अपनी तहरीर में बताया है कि ये लोग फोन करके धमकी देते थे कि यदि दहेज नहीं दिया गया तो उनकी बेटी को जान से मार देंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्हीं लोगों ने 7 जनवरी 2026 को उनकी बेटी को फांसी लगाकर मार डाला। अफसाना का एक तीन साल का बेटा भी है, जिसका नाम असद है। इस घटना से परिवार में गहरा शोक व्याप्त है।सलामुद्दीन ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी अफसाना का विवाह 10 नवंबर 2018 को जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के हीरापुर मचहटी निवासी सलमान पुत्र अजीम से किया था। विवाह के बाद से ही सलमान और उसके परिवार के अन्य सदस्य अफसाना से दहेज की मांग करने लगे थे।सलाउदुद्दीन ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की अपील की है। वही इस मामले में गुरुवार को जानकारी लेने पर क्षेत्राधिकारी अजीत कुमार रजक ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है मिलती है तो कार्यवाही किया जाएगा फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिय भेजा गया है रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि हत्या हुआ है या आत्महत्या है। लड़की के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुरे मामले की छानबीन करने के बाद ही कुछ स्पष्ट किया जाएगा।

बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, 5 बहनों में था इकलौता

गोरखपुर, (संवाददाता)। चौरचौरा में मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे निबियवहा ओवरब्रिज पर एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। देवरिया की तरफ से आ रही एक अनुबंधित बस और बाइक के बीच ओवरटेक के दौरान स्थिति बिगड़ गई, जिससे बाइक सवार असंतुलित होकर गिर पड़ा और बस का पहिया उसके चेहरे पर चढ़ गया। हादसे के बाद ओवरब्रिज पर अफरा–तफरी मच गई। ओवरब्रिज एक ही लेन का होने के कारण करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरीचौरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया। पुलिस ने आवश्यक पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना में शामिल बाइक और बस को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 20 वर्षीय आशीष मौर्या पुत्र कुबेर मौर्या, निवासी पीपरपाती, कोतवाली देवरिया के रूप में हुई है। परिजनों व रिश्तेदारों के अनुसार आशीष पांच बहनों में इकलौता भाई था। वह देवरिया से गोरखपुर अपनी बड़ी बहन के जन्मदिन समारोह में शामिल होने आ रहा था, तभी यह हादसा हो गया। आशीष बीआरडी इंटर कॉलेज देवरिया में कक्षा 12 का छात्र था। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाना तहसील प्रशासन के लिए बना टेढ़ी खीर

सुलतानपुर, (संवाददाता)। जिले की बल्दीराय तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाना तहसील प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। तालाब, खलिहान, नाली, चकरोड, घूर, गड्ढा, नवीन परती सहित अन्य सरकारी भूमि पर दबंगों का कब्जा वर्षों से बना हुआ है, लेकिन प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में असफल नजर आ रहा है। स्थिति यह है कि योगी सरकार और उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद तहसील प्रशासन कब्जेदारों को पूरी तरह बेदखल कराने में नाकाम साबित हो रहा है। कई मामलों में न्यायालय अथवा राजस्व न्यायालय से आदेश होने के बाद भी मौके से अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सका है।

अब 30.20 लाख नए मतदाता, पहले ये 36. 66 लाख- 6.45 लाख नाम सूची से हटेंगे

गोरखपुर, (संवाददाता)। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मंगलवार को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। जिले में 6,45, 425 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जबकि 3,22,468 की मैपिंग नहीं हुई है। कुल मतदाताओं की संख्या अब 30,20,908 है। अब एक माह तक दावों–आपत्तियों का दौर चलेगा। इस दौरान प्राप्त आवेदनों की जांच करके सुधार किए जाएंगे। डीएम दीपक मीणा ने पर्यटन भवन स्थित कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में एसआईआर की अगली प्रक्रिया की जानकारी दी। इसके बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में बताया कि छह फरवरी तक दावों–आपत्तियों को प्राप्त किया

जाएगा, जबकि 27 फरवरी तक सुनवाई और सत्यापन करके संशोधित किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची छह मार्च को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि बीएलओ बूथों पर बैठेंगे और घर–घर जाकर बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस देकर दस्तावेज मांगेंगे। अलग–अलग उम्र के अनुसार मतदाताओं को स्वयं के साथ माता–पिता या दोनों में किसी एक के दस्तावेज भी जमा करने होंगे। दावों–आपत्तियों में मतदाता अपने नाम के कटने, अपात्र के सूची शामिल होने के साथ नाम या पते में सुधार के आवेदन दिए जाएंगे। नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म–6, संशोधन के लिए फॉर्म–8 या सात भर सकते हैं। इन सभी फॉर्म के साथ एसआईआर का घोषणा पत्र भी भरना है, इसकी अंतिम तारीख छह फरवरी है। अनंतिम मतदाता सूची के अनुसार जिले में 16,69,629 पुरुष और 13,51,082 महिला मतदाता हैं। अन्य श्रेणी में 197 मतदाता हैं। सभी बीएलओ को मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है। डीएम ने बताया कि एसआईआर में एक बूथ पर 1200 मतदाता से अधिक नहीं होंगे। इस मानक को पूरा करने में जिले में 368 बूथ बढ़ गए हैं। अब बूथों की संख्या 4047 हो गई है, जबकि पहले 3679 बूथ ही थे। इसी तरह 13 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में सबसे ज्यादा चिल्लूपार में 50, जबकि सबसे कम कैंपियरगंज में आठ बूथ बढ़ाए गए हैं। अब कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2078 हो गई है। नए बूथों पर नए बीएलओ एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करते हुए कार्य करेंगे। 17.61 प्रतिशत मतदाताओं के नाम कटेंगे मतदाता सूची के अनुसार, 17. 61 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।